91/8/908

जनसत्ता
पृ० (1+8)
30-07-2014

पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों तक पहुंचे तकनीक : मोदी

मछली पालन में 'नील क्रांति' की भी जरूरत बताई प्रधानमंत्री ने

नई दिल्ली, 29 जुलाई (भाषा)। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ाने पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 'प्रयोगशाला से खेत तक' का नारा दिया। मोदी ने कहा कि किसानों की आय तभी बढ़ेगी जब वे तभी देश और दुनिया का पेट भर सकेंगे जब वे अपना उत्पादन बढ़ाने की स्थिति में होंगे।

प्रधानमंत्री ने 'कम जमीन और कम समय' में कृषि उत्पादन को बढ़ाने में मदद के लिए वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने घटते प्राकृतिक संसाधनों और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बारे में चिंता का इजहार किया। प्रधानमंत्री ने हरित और श्वेत क्रांति की तर्ज पर देश में मत्स्य पालन के क्षेत्र में 'नील क्रांति' का आह्वान किया।

यहां भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर) के 86वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा- हमें दो चीजें साबित करनी है। एक तो यह कि हमारे किसान पूरे देश और दुनिया को अनाज मुहैया कराने में समर्थ हैं और दूसरे कृषि हमारे किसानों को पर्याप्त आय उपलब्ध करा सकती है। खाद्य तेल और दलहन के लिए देश की अब तक भी आयात पर अत्यधिक निर्भरता पर चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है और प्रयास होना चाहिए कि हम कृषि जिंसों के मामले में आत्मनिर्भर हों।

मोदी ने इसी संदर्भ में कहा- हमारा ध्येय वाक्य होना चाहिए, प्रति बूंद, अधिक फसल। प्रधानमंत्री ने कृषि अनुसंधान को प्रयोगशालाओं से खेतों तक पहुंचाने (लैंड टू लैब) की चुनौती का समाधान निकालने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि किसानों को नई प्रौद्योगिकी के लाभ को सहज तरीके से समझाने के प्रयास किए जाने चाहिए।

मोदी ने आइसीएआर के कृषि वैज्ञानिकों से संस्था के शताब्दी समारोह योजना बनाने को कहा और उनसे अपील की कि शताब्दी समारोह के लिए बचे 14 साल में

बाकी पेज 8 पर

जीएम फसलों के परीक्षण का विरोध

नई दिल्ली, 29 जुलाई (भाषा)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े दो संगठनों ने मंगलवार को पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात के बाद दावा किया कि जैव प्रौद्योगिकी नियामक एजंसी (जीईएसी) से स्वीकृत कुछ जीएम फसलों के खेतों में परीक्षण पर रोक लगा दी गई है। लेकिन सरकार ने कहा है कि इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। स्वदेशी जागरण मंच और भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों ने जावड़ेकर से मुलाकात की और धान, बैगन और कपास की कुछ जीएम प्रजातियों के खेत परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। इन संगठनों ने उन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी (जीईएसी) की ओर से इस महीने के शुरू में

बाकी पेज 8 पर

पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों तक पहुंचे तकनीकः मोदी

पेज 1 का बाकी

संस्थान पिछले 86 साल की उपलब्धियों से अधिक उपलब्धियां हासिल करने की योजना बनाई जाए। उन्होंने कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक शोधों को किसानों तक पहुंचाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कृषि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों द्वारा रेडियो स्टेशनों की स्थापना करने का सुझाव दिया ताकि किसानों के बीच में जागरूकता बढ़ाई जा सके। मोदी ने कहा कि जब तक किसानों की आय नहीं बढ़ेगी तब तक कृषि विकास के लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इस कारण सरकार की नीतियां इस दिशा में निर्देशित होनी चाहिए।

मोदी ने कहा-अनाजों की भारी मांग है और यह हमारे लिए एक अवसर है। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि कैसे कृषि शोध को प्रयोगशाला से खेत तक पहुंचाया जाए। अगर शोध का काम खेतों तक नहीं पहुंचता है तो हमें वांच्छित परिणाम नहीं मिल सकते।

प्रधानमंत्री ने कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि महाविद्यालयों को रेडियो स्टेशन शुरु करने का आह्वान करते हुए कहा कि युवा शिक्षित और प्रगतिशील किसान और कृषि शोध में लगे विद्वान मिल कर प्रतिभाओं की एक अच्छा समूह खड़ा कर सकते हैं। उन्होंने आइसीएआर को अगले चार-पांच साल में देश में सभी कृषि शोधों के आंकड़ों का डिजीटलीकरण करने को कहा। देश में नील क्रांति (मत्स्य क्रांति) हासिल करने की आवश्यकता के विषय में मोदी ने कहा-भारत के तिरंगा झंडे में, हम हरित और श्वेत क्रांति के बारे में बात करते हैं लेकिन नीले रंग का अशोक चक्र भी है। उस क्रांति के बारे में भी हमें गौर करना होगा। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन क्षेत्र का विकास भी जरूरी है क्योंकि इसका विशाल वैश्विक बाजार है और इसमें मछुआरों के जीवन को बदलने की क्षमता है। उन्होंने समुद्री शैवालों के लिए व्यापक शोध और संवर्धन किये जाने का भी आह्वान किया।

दलहनों और खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भी दलहनों और तिलहनों के आयात को कम करना बड़ी चुनौती है और इसकी उत्पादकता को बढ़ाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। निर्धन से निर्धन व्यक्ति को दलहन मिलना चाहिए जिसमें अधिक प्रोटीन होता है। हमें इस दिशा में काम करने की जरूरत है। कृषि अर्थव्यवस्था होने के बावजूद खाद्य तेलों की जरूरत के लिए इसके आयात पर निर्भरता का उल्लेख करते हुए मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि वैज्ञानिकों और कृष्क समुदाय दोनों के द्वारा इसे चुनौती के बतौर लेन की जरूरत है ताकि इस मसले को संबोधित किया जा सके। मोदी ने आइसीएआर को हिमालय की औषधीय पौधों व वनस्पतियों की संभावनाओं का भी दोहन करने पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि इस मामले में चीन आगे है।

उन्होंने जल संकट से निपटने के लिए आइसीएआर को मौसम चक्र में बदलाव के मद्देनजर जल का प्रबंधन करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने को कहा। उन्होंने कहा- हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी का एक बूंद भी बर्बाद न हो। इस संदेश को आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने सवाल किया कि हम इस दिशा में कैसे काम करें।

जीएम फसलों के परीक्षण का विरोध

पेज 1 का बाकी

धान, बैंगन, मटर, सरसों और कपास की सुरक्षित घेरे में खेती के परीक्षण के 15 प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने के बारे में अपनी चिंताओं से अवगत कराया। उन्होंने दावा किया कि मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया है कि जीएम फसलों के खेत परीक्षण के बारे में फैसले पर रोक लगा दी गई है। दूसरी ओर पर्यावरण मंत्री जावड़ेकर ने इस बैठक की पुष्टि तो की, लेकिन साथ ही साफ किया कि सरकार ने इस विवादास्पद मुद्दे पर कोई फैसला नहीं किया है। उन्होंने कहा सरकार जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेगी।

प्रतिलिपि:-
1. निदेशक कार्यालय
2. संयुक्त निदेशक (प्रसार)
3. अधिष्ठाता/ सं. निदेशक (शिक्षा)
4. प्रभारी पी.पी. आई
5. प्रभारी वेबसाइट
6. प्रभारी यू.एस. आई

सुनीता गुप्ता 30/7/14
प्रभारी पत्रिका एवं समाचार पत्र अनुभाग